vishikhamedia@gmail.com

विभिन्न विषयों पर आधारित राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
RNI No. UTTHIN/2021/80704

_vishikhamedia/ vishikhamedia/ _vishikhamedia
vishikhamedia vishikhamedia.in

मूल्य:35 रुपये

तीर निशाने पर विशिखा

वर्ष:05 अंक:9 सितम्बर 2025 पृष्ठ:32

उत्तराखण्ड संस्करण

उत्तराखंडः धराली त्रासदी

तबाह गाँव अब सुरक्षित स्थान पर बसाया जाएगा

विशिखा

विशिखा न्यूज़ 24x7

आपकी बात, आपके साथ

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

तीर निशाने पर

विशिखा

अब डिजिटल एडिशन में भी उपलब्ध

www.vishikhamedia.in

अंदर

मोदी में है विषम परिस्थितियों में कड़े निर्णय लेने की क्षमता

05 | उत्तराखण्ड राज्य सरकार व नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच समझौता

12 | विपक्ष की चरित्र हनन और संवैधानिक संस्थाओं पर हमले वाली सियासत

14 | सपा में काफी पुराना है महिला अपमान का सिलसिला

16 | शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, संघ की पहली पसंद

18 | तेजस्वी राहुल को पीएम बनाने को तैयार लेकिन...

20 | मॉनसून में मच्छरों से हो सकता है डेंगू मलेरिया, बचाव के लिए तुरंत करें ये उपाय

21 | डब्ल्यूएचओ ने हेपेटाइटिस-डी को माना कैंसर का कारण, जानिए इससे बचने के उपाय

22 | मखाना के सहारे सीमांचल में वोट की फसल काटने उतरे राहुल

24 | योगी के तेवर ढीले पड़ते ही स्कूल-कॉलेजों के आसपास फिर मंडराने लगे रोमियों

26 | भारत ने नहीं झुकाया सिर ट्रंप की धमकी को दिया आंकड़ों से करारा जवाब

29 | भारत-चीन आये साथ, तो एशिया की राजनीति में होगा बड़ा उलट फेर

30 | राजस्थानः अब साल में केवल छह माह ही चलेंगे ईंट-भट्टे, सरकार ने जारी किए आदेश

विशिखा
तीर निशाने पर

अंक: 9 वर्ष: 06, सितम्बर 2025

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
प्रियल श्रीवास्तव
सम्पादक
अनिल कुमार श्रीवास्तव
डिजाइन
देवेन्द्र नेगी, उत्तराखण्ड

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक **अनिल कुमार श्रीवास्तव** द्वारा **भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, डी.बी. कॉर्प लिमिटेड** शिवदासपुरा, टोंक रोड, जयपुर से छपवाकर एवं **विशिखा मीडिया** सी-29, शिवलोक कॉलोनी, लाडपुर-राजपुर रोड, देहरादून 248008
उत्तराखण्ड से प्रकाशित

पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में प्रकाशित सामग्री के विषय में अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझाव अवश्य भेजें। अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझावों को आप हमें vishikhamedia@gmail.com पर ई-मेल भी कर सकते हैं।
लेखकों से निवेदन है कि कृपया अपनी स्व-लिखित एवं मौलिक रचनायें ही भेजें। रचनाओं के साथ अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल एवं फोटो अवश्य भेजें। रचनाओं के छापने या न छापने का अधिकार संपादकीय मंडल का होगा। अस्वीकृत रचनायें लौटाई नहीं जाएंगी।
पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख एवं रचनाओं में संपादक की सहमति हो, यह आवश्यक नहीं है। पत्रिका में प्रकाशित आलेख एवं रचनायें लेखकों के निजी विचार हैं। प्रकाशित सामग्री के उपयोग करने से पूर्व में संपादक की लिखित सहमति आवश्यक है।
'किसी भी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर (राजस्थान) होगा।
'पत्रिका में प्रकाशित कुछ चित्र, लेख एवं आंकड़े को इन्टरनेट एवं अन्य वेबसाइट से लिया गया है।

विशिखा न्यूज़ 24x7
आपकी बात, आपके साथ

सम्पादक की कलम से

अनिल कुमार श्रीवास्तव

5 अगस्त को दोपहर 1रू45 बजे खीर गंगा नदी में आई अचानक बाढ़ ने महज 34 सेकंड में पूरे धराली गाँव को जमींदोज कर दिया। पर्यटकों के दबाव और अवैज्ञानिक निर्माण की वजह से आई आपदा के कारण उत्तरकाशी के धराली गाँव में बादल फटने और भीषण भूस्खलन से हुई तबाही के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि धराली को उसकी पुरानी जगह पर दोबारा नहीं बसाया जाएगा। गाँव का पुनर्वास अब किसी सुरक्षित स्थान पर किया जाएगा। साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि नदियों के किनारे और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में कोई नया निर्माण नहीं होगा। चूँकि पिछले 10 वर्षो में धराली तीन बार आपदाओं की चपेट में आ चुका है। और हर बार उजड़ने के बावजूद ग्रामीण वहाँ नए निर्माण कर लेते थे, लेकिन इस बार की त्रासदी ने पूरे गाँव को मिट्टी में मिला दिया है।

धराली गाँव का दृश्य अब भी दिल दहला देने वाला है। होटल, घर, गाड़ियाँ सब मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। वहां तक पहुँचने का एकमात्र साधन इस वक्त सिर्फ हेलिकॉप्टर है। राहत कार्य बारिश से प्रभावित हो रहे हैं। मलबा हटाने पर होटल, वाहन, पर्स और व्यक्तिगत सामान मिल रहे हैं। गाँव का बड़ा हिस्सा अब दलदल में बदल चुका है। धराली गाँव का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो चुका है, नदी का रुख बदल गया है और अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। जीवित बचे लोगों की तलाश की उम्मीदें धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही हैं। इसीलिए कहते हैं इंसान को कभी भी प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए...

शेष फिर....

राज्य सरकार व नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच समझौता

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में पर्वतमाला परियोजना के अन्तर्गत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे के विकास के लिए राज्य सरकार और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच समझौता हुआ।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में मंगलवार को सचिवालय में पर्वतमाला परियोजना के अन्तर्गत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे के विकास के लिए राज्य सरकार और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के अन्तर्गत इक्विटी भागीदारी में एनएचएलएमएल की 51 प्रतिशत और राज्य सरकार की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

राजस्व साझेदारी के अन्तर्गत 90 प्रतिशत धनराशि उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन, परिवहन एवं गतिशीलता के क्षेत्र में व्यय की जायेगी। इस समझौते के अवसर पर राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, भारत सरकार श्री अजय टम्टा एवं उत्तराखण्ड के पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह समझौता प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पटल पर नई पहचान दिलाने के साथ ही पर्यटन, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी

राजस्व साझेदारी के अन्तर्गत ९० प्रतिशत धनराशि उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन, परिवहन एवं गतिशीलता के क्षेत्र में व्यय की जायेगी। इस समझौते के अवसर पर राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, भारत सरकार अजय टम्टा एवं उत्तराखण्ड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी उपस्थित थे।

ढ़ाचे के क्षेत्र में नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच लगभग 4100 करोड रूपए की लागत से 12.9 किलोमीटर लंबी तथा गोविंदघाट से हेमकुण्ड साहिब के बीच 2700 करोड़ से अधिक की लागत की 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य में रोपवे कनेक्टिविटी के विस्तार में नए आयाम स्थापित करने के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में रेल, रोड और रोपवे कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। चारधाम ऑलवेदर रोड, दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, सितारगंज से टनकपुर मोटर मार्ग, पौंटा साहिब देहरादून, बनबसा से कंचनपुर, भानियावाला से ऋषिकेश, काठगोदाम से लालकुंआ, हल्द्वानी बाईपास और सीमांत क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी को सशक्त करने की दिशा में कार्य हो रहे हैं। रेल कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी तेजी से कार्य हो रहे हैं। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा ने कहा कि राज्य में रोपवे के विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में हर क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। इन रोपवे के निर्माण के बाद श्रद्धालुओं को केदारनाथ और हेमकुण्ड साहिब के दर्शन करने में काफी सुगमता होगी। पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा कि यह समझौता राज्य में पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। इन रोपवे के निर्माण के बाद स्थानीय स्तर पर लोगों की आर्थिकी और रोजगार में वृद्धि होगी।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, अपर सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग, भारत सरकार श्री विनय कुमार, सचिव श्री दिलीप जावलकर, श्री धीराज गर्ब्याल, श्री राजेश मलिक, वाइस प्रेजीटेंट, रोपवे एनएचएलएमएल श्री प्रशांत जैन, अपर सचिव श्री अभिषेक रोहिला और पर्यटन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखंड: धराली त्रासदी

तबाह गाँव अब सुरक्षित स्थान पर बसाया जाएगा

मुख्यमंत्री आवास में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह तय किया गया कि धराली को उसकी पुरानी जगह पर दोबारा नहीं बसाया जाएगा। गाँव का पुनर्वास किसी सुरक्षित स्थान पर किया जाएगा।

उत्तरकाशी के धराली गाँव में बादल फटने और भीषण भूस्खलन से हुई तबाही के बाद सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री आवास में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह तय किया गया कि धराली को उसकी पुरानी जगह पर दोबारा नहीं बसाया जाएगा। गाँव का पुनर्वास किसी सुरक्षित स्थान पर किया जाएगा।

अब गाँव नहीं बसाया जाएगा पुराने स्थान पर

सरकार ने साफ कर दिया है कि नदियों के किनारे और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में कोई नया निर्माण नहीं होगा। धराली की तरह अन्य संवेदनशील गाँवों को भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है। पिछले 10 वर्षों में धराली तीन बार आपदाओं की चपेट में आ चुका है। हर बार उजड़ने के बावजूद ग्रामीणों ने वहाँ नए निर्माण कर लिए थे। इस बार की त्रासदी ने पूरे गाँव को मिट्टी में मिला दिया है।

विस्थापन और पुनर्वास की तैयारी

अपर सचिव बंशीधर तिवारी के अनुसार, विस्थापन को लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत शुरू हो गई है। ग्रामीण चाहते हैं कि उन्हें 8 से 12 किलोमीटर दूर लंका, कोपांग या जांगला में बसाया जाए। इस आपदा में सेना का कैंप भी बह गया था। नया कैंप कहाँ बनेगा, इसके लिए सेना श्रीखंड पर्वत, आसपास के ग्लेशियर और झीलों का सर्वे कर रही है।

गाँव की हालतः तबाही की गवाही

गाँव का दृश्य अब भी दिल दहला देने वाला है। होटल, घर, गाड़ियाँ सब मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। सड़क मार्ग अभी तक नहीं खुल पाया है और पहुँचने का एकमात्र साधन हेलिकॉप्टर है। राहत कार्य बार–बार बारिश से प्रभावित हो रहे हैं। मलबा हटाने पर होटल, वाहन, पर्स और व्यक्तिगत सामान मिल रहे हैं। गाँव का बड़ा हिस्सा अब दलदल में बदल चुका है।

स्थानीय लोग मानते हैं कि पर्यटकों के दबाव और अवैज्ञानिक निर्माण ने आपदा की भयावहता बढ़ा दी। कई परिवार पहले ही भाग गए थे, लेकिन दर्जनों लोग बाढ़ में फँस गए। पीड़ितों को सरकार की ओर से पाँच लाख रुपये की आर्थिक सहायता और आवश्यक सामान दिया जा रहा है।

रेस्क्यू अभियान जारी

धराली और हर्षिल में अब तक 1,300 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। सेना और एनडीआरएफ हाई–टेक मशीनों, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (ळच्च्), स्पक्।त सर्वे और स्निफर डॉग्स की मदद से खोज अभियान चला रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, मलबे में 8–10 फीट नीचे होटल और लोग दबे हुए हैं।

सेना ने अस्थायी रास्ते और रोप–वे बनाने की योजना बनाई है ताकि राहत सामग्री पहुँचाई जा सके। क्षेत्र को चार सेक्टरों में बाँटकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मलबा हटाने और शवों की तलाश कर रही हैं। अब तक दो शव बरामद हुए हैं, जिनमें एक सेना का जवान भी शामिल है।

पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत कार्यों की समीक्षा की। धराली गाँव का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो चुका है, नदी का रुख बदल गया है और अब भी सौ से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका है। जीवित बचे लोगों की तलाश की उम्मीदें धीरे–धीरे क्षीण होती जा रही हैं।

34 सेकंड में जमींदोज हुआ गाँव

5 अगस्त को दोपहर 1रू45 बजे खीर गंगा नदी में आई अचानक बाढ़ ने महज 34 सेकंड में पूरे धराली गाँव को जमींदोज कर दिया। घटना के सात दिन बाद भी गाँव लाखों टन मलबे के नीचे दबा हुआ है। अब तक 43 लोग लापता हैं, जिनमें से केवल एक शव बरामद हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कम से कम 100 लोग मलबे के नीचे दबे हैं।

मोदी में है विषम परिस्थितियों में कड़े निर्णय लेने की क्षमता

भारत के बढ़ते कदमों को रोकने के लिये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों द्वारा भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों की साजिश रची जा रही है।

संजय सक्सेना
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

देश–दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा हिन्दुस्तान कुछ देसी–विदेशी ताकतों की आंख की किरकिरी बन गया है। विदेशी ताकतों के साथ–साथ हमारे देश के कुछ नेताओं एवं सामाजिक संगठनों को भी आगे बढ़ता भारत रास नहीं आ रहा है। विश्व की राजनीतिक हवाएं भारत के खिलाफ तेजी से बह रही थीं। इसके पीछे इन देशों के कुछ आर्थिक या राजनीतिक कारण हो सकते हैं लेकिन अपने ही देश को खाकर अपने ही देश को नीचा दिखाने में लगे रहने वालों के रवैये पर आश्चर्य होता है।

भारत के बढ़ते कदमों को रोकने के लिये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों द्वारा भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों की साजिश रची जा रही है।

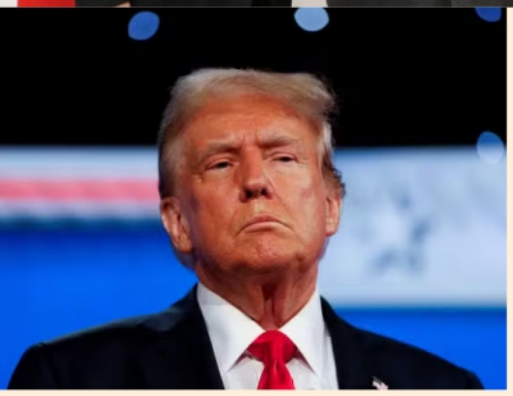

अजब तमाशा देखने को मिल रहा है कि जो अमेरिका अपने दुश्मन देश रूस से तमाम चीजें आयात करता है, वही भारत पर इस बात का दबाव डाल रहा है कि वह रूस की जगह अमेरिका से तेल खरीदे। ऐसा नहीं करने पर अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर 50 फीसदी टैरिफ ठोक दी गई। क्योंकि अमेरिका के दबाव के बाद भी भारत ने रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बनाए रखा था। जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका अपने कुछ उत्पाद, जिसमें मांसाहारी मिल्क प्रोडक्ट्स खासकर शामिल हैं, उसे भारत में खपाना चाहता है,

आज भी, २०२५ में, जब अंतरराष्ट्रीय दबाव से देश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, मोदी चट्टान के समान सामने खड़े नजर आ रहे हैं। मोदी जी का पहला सिद्धांत है डेटा आधारित निर्णय। वे कभी भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लेते। विपक्ष की नकारात्मक राजनीति से जनता भड़क रही हो, तो भी वे आंकड़ों पर भरोसा करते हैं।

लेकिन मोदी सरकार ने इससे साफ इंकार कर दिया तो कथित विश्व गुरु बौखला गया।

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा, तो वे जी–7 में भारत को अलग–थलग कर देंगे, उस पर टैरिफ लगा देंगे। ऐसे समय में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को देश और प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना चाहिये था, लेकिन विपक्षी नेता राहुल गांधी ट्विटर पर पोस्ट कर रहे थे, 'मोदी जी की विदेश नीति फेल हो गई है, जनता भुगत रही है।' दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे, जहां लोग 'मोदी हटाओ, देश बचाओ' के नारे लगा रहे थे। यह सब इंडिया गठबंधन के नेता करा रहे थे। वहीं इससे विचलित हुए बिना मोदी मीटिंग में हर मंत्री से सवाल पूछ रहे थे इन प्रतिबंधों का क्या विकल्प हैं? क्या प्रभाव पड़ेगा? उनका तरीका है सुनना, विश्लेषण करना और फिर निर्णय लेना। वे कहते हैं, राष्ट्रहित पहले। अंतरराष्ट्रीय दबाव से झुकना नहीं, बल्कि संवाद से समाधान निकालना होगा। उन्होंने निर्णय लिया कि भारत रूस के साथ व्यापार जारी रखेगा, लेकिन अमेरिका से बातचीत बढ़ाएगा।

इसी तरह से भारत को चीन की सीमा पर भी तनाव का सामना करना पड़ रहा था। उधर, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की घटनाएं फिर से सिर उठा रही थीं। देश के अंदर कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी सहित कई और दल भी नकारात्मक राजनीति पर उतर आए हैं।

वे जनता को भड़काने में लगे हैं। कभी देश के प्रधानमंत्री को 'चौकीदार चोर है' कहकर अपमानित किया जाता है तो कभी आरोप लगाया जाता है कि मोदी सरकार तानाशाही चला रही है। इसी के साथ जनता से ठुकराये गये कुछ नेता और राजनीतिक दल बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के समर्थन के नाम पर आंदोलनों और अराजकता फैलाने लगते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को हर कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मोदी इन विषम परिस्थितियों में कैसे काम करते हैं? कैसे लेते हैं महत्वपूर्ण निर्णय? यह यक्ष प्रश्न है, जहां दृढ़ता, रणनीति और राष्ट्रभक्ति की मिसाल मिलती है। इसको कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है।

एक बार, जब कोविड–19 महामारी के दौरान अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा था, डब्ल्यूएचओ और पश्चिमी देश भारत की वैक्सीन नीति पर सवाल उठा रहे थे। तब मोदी ने साहसिक निर्णय लिया था कि भारत स्वदेशी वैक्सीन पर फोकस करेगा। आज भी, 2025 में, जब

के समान सामने खड़े नजर आ रहे हैं। मोदी जी का पहला सिद्धांत है डेटा आधारित निर्णय। वे कभी भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लेते। विपक्ष की नकारात्मक राजनीति से जनता भड़क रही हो, तो भी वे आंकड़ों पर भरोसा करते हैं। किसान आंदोलन के दौरान, जब मोदी सरकार पर किसान–विरोधी होने का आरोप लगाया जा रहा था, तब मोदी ने कृषि विशेषज्ञों से रिपोर्ट मंगवाई और कानूनों को वापस लेने का फैसला किया न कि दबाव में, बल्कि लंबे विचार–विमर्श के बाद।

देश के अंदर की चुनौतियां और भी कठिन हैं। विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है। जनता को भड़काने के लिए फेक न्यूज फैला रहा है। जैसे, जब जम्मू–कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, विपक्ष ने कहा यह देश–विरोधी है, मुसलमानों के खिलाफ। प्रदर्शन हुए, अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भारत को बदनाम किया। लेकिन मोदी ने बिना विचलित हुए ग्राउंड लेवल पर टीम भेजी, स्थानीय

एक बार, जब कोविड-१९ महामारी के दौरान अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा था, डब्ल्यूएचओ और पश्चिमी देश भारत की वैक्सीन नीति पर सवाल उठा रहे थे। तब मोदी ने साहसिक निर्णय लिया था कि भारत स्वदेशी वैक्सीन पर फोकस करेगा।

नेताओं से बात की, विकास योजनाएं शुरू कीं। निर्णय लेते समय वे हमेशा दीर्घकालिक हितों का ध्यान रखते हैं। उनका तरीका है विपक्ष की राजनीति को अनदेखा कर, जनता के हित पर फोकस। वे रोजाना सोशल मीडिया मॉनिटर करते हैं न कि ट्रोल होने से डरकर, बल्कि जनता की नब्ज जानने के लिए। एक बार, जब हैशटैग 'फार्मर प्रोटेस्ट' ट्रेंड कर रहा था, उन्होंने खुद ट्वीट किया कि किसानों से बात हो रही है, समाधान निकलेगा। यह उनकी रणनीति है जनता से सीधा जुड़ना, विपक्ष के भड़कावे को बेअसर करना।

मोदी अकेले नहीं सोचते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से वे रोज बात करते हैं। जब चीन की सीमा पर एलएसी पर तनाव बढ़ा, अंतरराष्ट्रीय दबाव था कि भारत पीछे हटे। विपक्ष ने कहा मोदी जी ने देश बेच दिया। लेकिन मोदी ने सेना को मजबूत किया, डिप्लोमेसी बढ़ाई। गलवान घाटी की घटना के बाद, उन्होंने निर्णय लिया कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च दोगुना किया जाएगा। यह फैसला विषम परिस्थिति में लिया गया, जब अर्थव्यवस्था दबाव में थी। लेकिन मोदी कहते हैं सुरक्षा पहले, बाकी बाद में।

ऐसी परिस्थितियों में काम करने का उनका रहस्य है अनुशासन और विजन। 2025 में, जब क्लाइमेट चेंज पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा, पश्चिमी देश भारत से कोयला छोड़ने की मांग कर रहे थे। मोदी ने सीओपी सम्मेलन में घोषणा की कि भारत नेट जीरो का लक्ष्य रखेगा, लेकिन अपनी गति से। विपक्ष ने इसे झूठा वादा कहा, जनता को भड़काया। लेकिन मोदी जी ने घरेलू स्तर पर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स तेज किए। निर्णय लेते समय वे हमेशा बहुमत की राय नहीं सुनते, बल्कि सही क्या है, वह चुनते हैं। जैसे, डिमोनेटाइजेशन के दौरान, जब विपक्ष ने काला धन का शोर मचाया, मोदी जी ने कहा यह अर्थव्यवस्था को साफ करेगा। आज डिजिटल पेमेंट्स की सफलता उसका प्रमाण है।

मोदी जी की स्टोरी प्रेरणादायक है। गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का सफर आसान नहीं था। चाय बेचने वाले लड़के से विश्व नेता बनने में उन्होंने सीखा कि दबाव सहना पड़ता है। 2025 की इन विषम परिस्थितियों में, वे काम करते हैं सुबह योग से, दिन भर मीटिंग्स से, रात को प्लानिंग से। महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं डेटा, टीम और राष्ट्रहित पर आधारित।

विपक्ष की नकारात्मकता को वे चुनौती मानते हैं, जनता को भड़काने की कोशिशों को संवाद से काटते हैं। अंतरराष्ट्रीय दबाव से झुकते नहीं, बल्कि भारत की आवाज बुलंद करते हैं। उनकी दृढ़ता से भारत आगे बढ़ता है। कुल मिलाकर मोदी में है विषम परिस्थितियों

यूपीः आगरा में नकली दवाओं का काला कारोबार, ११ राज्यों तक फैला जाल

पकड़े जाने पर दवा व्यवसायी ने अधिकारियों को पेश की एक करोड़ की रिश्वत

आगरा से संचालित नकली दवाओं की सप्लाई का नेटवर्क 11 राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ से नशे वाली दवाओं के साथ–साथ सरकारी और एक्सपायर्ड दवाओं को री–पैक करके भेजा जाता है। खासतौर पर कफ सिरप की अवैध तस्करी बांग्लादेश तक हो रही है। मोती कटरा स्थित तीन मंजिला गोदाम में दवाओं का भारी भंडार मिला, जिसे देखकर जांच टीम भी हैरान रह गई।

गोदाम का संचालन हिमांशु अग्रवाल करता है, जो अपने परिजनों के नाम से खोली गई तीन अलग–अलग फर्मों के जरिए यह धंधा करता है। इनमें हे मां मेडिको प्राइवेट लिमिटेड, केएनके फार्मा प्राइवेट लिमिटेड और अन्य फर्म शामिल हैं। औषधि विभाग के सहायक आयुक्त अतुल उपाध्याय ने बताया कि गोदाम में तरह–तरह की दवाएं मिली हैं, जिनकी जांच के लिए कई जिलों की टीमें लगाई गई हैं।

पार्सल से होती थी सप्लाई

नकली दवाओं की खरीद–फरोख्त पार्सल के जरिये होती थी। कुरियर कंपनियों के कई कर्मचारी भी एसटीएफ की जांच के दायरे में आए हैं। ट्रेनों के माध्यम से दवाएं मंगवाकर इन्हें विभिन्न राज्यों तक पहुँचाया जाता था। छापेमारी के दौरान हिमांशु अग्रवाल ने रिश्वत देने के लिए एक करोड़ रुपये नकद से भरा बैग टीम के सामने रख दिया। फिलहाल, उसकी फर्मों और कर्मचारियों की भूमिका की गहन जांच हो रही है। हिमांशु अग्रवाल का नाम वर्ष 2022 में भी सामने आया था, जब गुजरात में पकड़े गए हवाला एजेंटों से आगरा कनेक्शन मिला था। उस समय आयकर विभाग ने नोटिस तो जारी किया, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब एसटीएफ इस पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही है। पूछताछ में सामने आया कि हिमांशु ने फव्वारा बाजार में एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी और फिर मोती कटरा में गोदाम व दुकान

खोलने के साथ कमला नगर में आलीशान कोठी व जमीन भी खरीदी।

11 राज्यों तक फैला कारोबार

पिछले 10 सालों में एसटीएफ, औषधि विभाग और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने लगभग 300 करोड़ रुपये की नकली दवाएं जब्त की हैं। उत्तर प्रदेश के जिलों के अलावा हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश तक इन दवाओं की सप्लाई होती थी। कई बार आगरा के गोदामों और मेडिकल एजेंसियों पर छापे भी पड़े, जिनमें नकली दवाओं की फैक्टरियां पकड़ी गईं।

पिछले वर्षों की बड़ी कार्रवाइयाँ

- 2025: नुनिहाई में ऑटो से जा रही नशे की दवाएं पकड़ी गईं।
- 2025: ताजगंज में पप्पू और इदरीश के घर बने गोदाम से अवैध दवाएं बरामद।
- 2024: शास्त्रीपुरम में नकली पशु–औषधि बनाने की फैक्टरी जब्त।
- 2024: कमला नगर निवासी विजय गोयल की चार नकली दवा फैक्टरियाँ पकड़ी गईं।
- 2022: मोहित बंसल की हिमाचल प्रदेश (बद्दी) में चल रही फैक्टरी पकड़ी गई।
- 2021: आवास विकास कॉलोनी व गढ़ी भदौरिया में नकली व एक्सपायर्ड दवाओं की फैक्टरियाँ बंद कराई गईं।
- 2018–2019: कई गोदामों और एजेंसियों से भारी मात्रा में नकली व सरकारी दवाओं की बरामदगी।

इस तरह हुई कार्रवाई

- शुक्रवार दोपहर 12 बजे छापेमारी शुरू हुई।
- शाम 6 बजे तक छह गोदामों पर कार्रवाई।
- रात 10 बजे चार गोदाम और मेडिकल स्टोर सील।
- शनिवार सुबह मोती कटरा गोदाम पर छापा।
- रात को हिमांशु अग्रवाल ने एक करोड़ रुपये रिश्वत में देने की कोशिश की।

उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और रविवार को भी कार्रवाई जारी रही।

विपक्ष की चरित्र हनन और संवैधानिक संस्थाओं पर हमले वाली सियासत

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके सहयोगी, ने उनकी प्रधानमंत्री छवि को धूमिल करने के लिए आरोपों का एक जाल बुना है, जो उन्हें भ्रष्टाचार-मुक्त और राष्ट्र के प्रति समर्पित नेता के रूप में कमजोर करने की कोशिश करता है।

अजय कुमार
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें उनके शुभचिंतक अक्सर भारत के पुनर्जनन के अडिग रचनाकार के रूप में चित्रित करते हैं, उन्होंने जब से सत्ता संभाली है, वह विपक्ष की तमाम साजिशों के 'तूफान' के केंद्र में खड़े हैं। उनके आलोचक, मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके सहयोगी, ने उनकी छवि को धूमिल करने के लिए आरोपों का एक जाल बुना है, जो उन्हें भ्रष्टाचार–मुक्त और राष्ट्र के प्रति समर्पित नेता के रूप में कमजोर करने की कोशिश करता है। यह केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं हैय कुछ इसे एक सुनियोजित साजिश के रूप में देखते हैं, जिसका उद्देश्य संवैधानिक संस्थाओं को कीचड़ में घसीटकर और उन्हें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कठपुतली बताकर मोदी में जनता का विश्वास तोड़ना है। विपक्ष की रणनीति, जो चुनावी असफलताओं के बाद हताशा से भरी है, में लगातार आरोप लगाना शामिल है, जो मोदी को लोकतंत्र के स्तंभों, जैसे चुनाव आयोग (ईसी) से लेकर सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों तक, का हेरफेर करने वाला बताते हैं।

इस कथित साजिश की जड़ें 2014, 2019 और 2024 में मोदी की भारी जीत तक जाती हैं, जिन्होंने विपक्ष को हक्का–बक्का कर दिया। विकास और राष्ट्रवाद पर उनकी अपील का मुकाबला करने में असमर्थ, विपक्ष ने मोदी के चरित्र हनन की रणनीति अपनाई। राफेल सौदे का विवाद इसका उदाहरण है। राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने मोदी पर पक्षपात का आरोप लगाया, दावा किया कि विमान खरीद में उनके उद्योगपति मित्रों को फाय दा पहुंचाया गया। अदालतों ने इन दावों को खारिज कर दिया, लेकिन यह साजिश महीनों तक सोशल मीडिया और विदेशी रिपोर्टों के जरिए गूंजती रही। राहुल गांधी इस साजिश के अगुआ थे। इसके बाद विपक्ष, खासकर राहुल गांधी ने 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च की अदानी समूह पर रिपोर्ट का सहारा लिया, जिसमें स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया गया और मोदी सरकार को जोड़ा गया, जिससे संसद में हंगामा हुआ। विपक्षी नेताओं ने जांच की मांग की, यह संकेत देते हुए कि मोदी अपने मित्रों को बचा रहे हैं, जबकि प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ एजेंसियों को हथियार बनाया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ताओं ने इसका जवाब दिया कि यह एक विदेशी–प्रायोजित स्मीयर कैंपेन है, जिसमें सेबी की अध्यक्ष मधबी पुरी बुच ने आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया। फिर भी, विपक्ष ने इसे व्यापक साजिश के साथ जोड़कर मोदी की स्वच्छ छवि पर हमला जारी रखा।

इस रणनीति का केंद्र संवैधानिक संस्थाओं पर हमला है। विपक्ष ने बार–बार ईडी और सीबीआई को पिंजरे का तोता करार दिया, यह आरोप लगाते हुए कि वे मोदी के नियंत्रण में हैं। 2023 में, 14 विपक्षी दलों ने इन एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें मनीष सिसोदिया और हेमंत सोरेन जैसे नेताओं

की गिरफ्तारी को बदले की राजनीति बताया। उन्होंने दावा किया कि 95 फीसदी मामले विपक्षी नेताओं पर हैं, जो संघवाद को कमजोर करते हैं। मोदी ने इसे भ्रष्टों का एकजुट होना कहकर खारिज किया, लेकिन कांग्रेस जैसे आलोचकों ने इसे लोकतंत्र का व्यवस्थित क्षरण बताया। न्यायपालिका भी अछूती नहीं रहीय विपक्षी आवाजों ने सरकार के पक्ष में फैसलों पर सवाल उठाए, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) को बरकरार रखने से लेकर एजेंसी दुरुपयोग की याचिकाओं पर सुनवाई में देरी तक। सुप्रीम कोर्ट को भी घसीटा गया, यह आरोप लगाकर कि यह कार्यपालिका से प्रभावित है, हालांकि कोर्ट ने ऐसे दावों को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज किया।

2014 में मोदी को मिली शानदार जीत के बाद चुनाव आयोग को विपक्ष के सबसे तीखे हमले झेलने पड़े हैं। 2019 के चुनावों के बाद, विपक्षी दलों ने ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया, कागजी मतपत्रों की वापसी की मांग की। राहुल गांधी और सहयोगियों ने 2024 के चुनावों में इसे और बढ़ाया, यह संकेत देते हुए कि मोदी की जीत में हेराफेरी हुई। अब बिहार चुनाव से पूर्व जब चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है तो उस पर वोटों की चोरी करने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर राहुल गांधी की टीम सारी हदें पार करती जा रही है। मोदी विरोधी राजनीति के चलते ही विपक्ष ने 2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया, इसे

आज भी, २०२५ में, जब अंतरराष्ट्रीय दबाव से देश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, मोदी चट्टान के समान सामने खड़े नजर आ रहे हैं। मोदी जी का पहला सिद्धांत है डेटा आधारित निर्णय। वे कभी भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लेते। विपक्ष की नकारात्मक राजनीति से जनता भड़क रही हो, तो भी वे आंकड़ों पर भरोसा करते हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी महिला हैं, का अपमान बताया, जबकि इससे पहले वे उनकी नियुक्ति का अपमान कर चुके थे। अमित शाह जैसे भाजपा नेताओं ने इसे पाखंड बताया, जो संस्थानों को बदनाम करने और मोदी की वैश्विक छवि को धूमिल करने की व्यापक साजिश का हिस्सा है। विदेशी तत्व आग में घी डालते हैं। 2023 में बीबीसी की 2002 के गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री ने पुराने जख्मों को कुरेदा, जिसके खिलाफ भाजपा शासित राज्यों ने इसे अंतरराष्ट्रीय साजिश बताकर प्रस्ताव पारित किए। ऐसी रिपोर्टों पर विपक्ष की खुशी ने केवल जॉर्ज सोरोस जैसे समूहों के साथ मिलीभगत की धारणा को मजबूत किया, जो भारत को कमजोर करने की कोशिश में हैं। जैसा कि भाजपा इसे देखती है, सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मंचों तक फैली है। राहुल गांधी के 2023–24 में अमेरिका में दिए भाषणों ने मोदी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताकर वैश्विक तानाशाहों से तुलना की। घरेलू स्तर पर, विपक्ष का 'अघोषित आपातकाल' का तंज मोदी के 11 साल के शासन पर गिरफ्तारियों और मीडिया पर अंकुश को उजागर करता है, लेकिन भाजपा आंकड़ों के साथ जवाब देती है। एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, और सजा अदालतों में बरकरार रहती है। विडंबना यह है कि जहां मोदी आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं विपक्ष विदेशों में, जैसे विदेशी राजदूतों से मिलकर मोदी–विरोधी साजिश को अंजाम देने में लगे हैं, जिसे राष्ट्रीय हितों के साथ विपक्ष का विश्वासघात माना जाता है। इसका परिणाम गहरा है। मोदी की स्वीकृति रेटिंग 2030 तक आर्थिक विकास के अनुमानों के साथ ऊंची बनी हुई है, लेकिन निरंतर शोर संस्थागत विश्वास को कमजोर करता है। आलोचकों का तर्क है कि यह विपक्षी रणनीति उलटी पड़ रही है, जो मतदाताओं को इससे दूर कर रही है, जो इसे हताशा का परिणाम मानते हैं। फिर भी, ध्रुवीकृत भारत में, यह विभाजन को बनाए रखता है। जैसा कि मोदी ने अपने 2025 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में संकेत दिया, जीएसटी में कमी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए, विपक्ष का व्यक्तिगत हमलों पर ध्यान उन्हें और अलग–थलग कर सकता है। क्या यह साजिश इस दिग्गज को गिरा देगी, या विपक्ष की हताशा को उजागर करेगी? दिल्ली के सत्ता के खेल में, सत्य अक्सर बयानबाजी की परतों के नीचे दब जाता है, एक बात स्पष्ट है मोदी की छवि के लिए यह लड़ाई भारत की आत्मा के लिए

सपा में काफी पुराना है महिला अपमान का सिलसिला

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की लगातार महिला विरोधी छवि ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को सोचने को मजबूर कर दिया है कि वह महिला स्वाभिमान के प्रति ज्यादा लचीला रूख अख्तियार करें

अजय कुमार
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

समाजवादी पार्टी (सपा) जिसकी स्थापना मुलायम सिंह यादव ने की थी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेताजी मुलायम सिंह यादव की तूती बोलती थी। लेकिन समय–समय पर इस पार्टी पर महिलाओं का सम्मान न करने और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। यह सिलसिला मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव तक जारी है। महिलाओं का अपमान करने के तमाम आरोप न केवल पार्टी नेताओं के बयानों से उपजे हैं, बल्कि उनके कार्यों और नीतियों से भी जुड़े हैं। विपक्षी दल, खासकर भाजपा इन मुद्दों को उठाकर सपा को महिला विरोधी करार देती रही है। समाजवादी पार्टी पर महिलाओं के अपमान के तमाम ऐसे आरोप लगे, जो समय–समय पर पार्टी की छवि को धूमिल करते रहे।

सबसे चर्चित उदाहरण 2014 का है, जब मुलायम सिंह यादव ने मुरादाबाद में एक रैली के दौरान बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा पर सवाल उठाते हुए कहा था, लड़के हैं, गलती हो जाती है। इस बयान ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। मीडिया और महिला अधिकार संगठनों ने इसे महिलाओं के प्रति असंवेदनशील बताया, क्योंकि यह बलात्कार जैसे गंभीर अपराध को गलती मानकर हल्का कर रहा था। मुलायम के इस बयान की वजह से सपा पर आरोप लगा कि पार्टी महिलाओं की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेती। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी इसे प्रो–रेपिस्ट रुख बताया, जिससे पार्टी की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा।

महिलाओं के अपमान को लेकर सपा के एक और प्रमुख नेता आजम खान भी विवादों में घिरे रहे हैं। 2019 में रामपुर लोकसभा चुनाव के दौरान, आजम ने भाजपा उम्मीदवार जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने खाकी अंडरवियर का जिक्र किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे अत्यंत अपमानजनक बताते हुए नोटिस जारी किया। इससे पहले, संसद में भाजपा सांसद रमा देवी पर भी आजम ने सेक्सिस्ट कमेंट किया, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी। इन बयानों ने सपा पर आरोप लगाया कि पार्टी के नेता महिलाओं को सम्मान नहीं देते और चुनावी फायदे के लिए अपमानजनक

भाषा का इस्तेमाल करते हैं।

2017 के विधानसभा चुनावों में सपा पर और बड़ा आरोप लगा जब कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति पर बलात्कार का केस दर्ज हुआ। एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी ने प्रजापति पर गैंगरेप का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन सपा पर आरोप था कि पार्टी ने आरोपी को संरक्षण दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सपा को बलात्कारियों का संरक्षक कहा, और महिलाओं की असुरक्षा का मुद्दा चुनावी बहस का केंद्र बना। हाल के वर्षों में भी ऐसे आरोप जारी हैं। 2024 में अयोध्या बलात्कार कांड में सपा नेता मोइन खान पर 12 साल की बच्ची से बलात्कार का आरोप लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा को महिलाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया, और पुराने बयानों का जिक्र किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि सपा अपराधियों को बचाती है, जबकि सपा ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। ये घटनाएं सपा की छवि को काफी प्रभावित करती रही हैं। परिणाम यह हुआ कि पार्टी ने जब महिलाओं के लिए योजनाएं चलाईं, जैसे स्त्री सम्मान समृद्धि योजना, लेकिन आरोपों ने उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। जब महिलाओं का सम्मान राजनीति का मूल होना चाहिए, तब ऐसे विवादों से समाज में असमानता बढ़ती है। सपा को इन आरोपों से सीख लेकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, वरना राजनीतिक नुकसान जारी रहेगा।

बात आज के माहौल की कि जाये तो

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की चायल सीट से विधायक पूजा पाल का मुद्दा तब गरमाया, जब सपा ने विधायक पूजा पाल को सीएम आदित्यनाथ की तारीफ करने के चलते उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया. इस एक्शन को सपा नेता सही बता रहे हैं, तो बीजेपी ने अखिलेश को घेरना शुरू कर दिया है।

2027 में जब सपा उत्तर प्रदेश की गद्दी पर काबिज होने का सपना देख रही है, तब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की लगातार महिला विरोधी छवि ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को सोचने को मजबूर कर दिया है कि वह महिला स्वाभिमान के प्रति ज्यादा लचीला रूख अख्तियार करें। वर्ना 2027 के विधान सभा चुनाव में उनको महिला वोटरों से बड़ा झटका मिल सकता है। मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में जिस तरह से अखिलेश अपनी ही पार्टी की महिला नेताओं का न केवल अपमान बर्दास्त करते जा रहे हैं बल्कि विधायक पूजा पाल को पार्टी से निकाल कर अखिलेश ने यह भी साबित कर दिया है कि उनको यह भी अच्छा नहीं लगता है कि उनकी विधायक पूजा पाल जिसके विधायक पति राजू पाल की माफिया अतीक अहमद ने हत्या करा दी थी, वह अतीक के खिलाफ मुंह खोलें। उनको जिस महिला का सुहाग उजाड़ दिया गया उसका दर्द समझने की बजाये इस बात की चिंता हो रही है कि अतीक के खिलाफ पूजा पाल के विधान सभा के अंदर दिये गये बयान से मुस्लिम वोटर नाराज नहीं हो जायें, इस लिये बिना किसी कारण बताओ नोटिस दिये पूजा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इससे पूर्व अखिलेश ने अपनी सांसद पत्नी डिंपल यादव के अपमान पर भी अपना मुंह उस समय बंद रखा था जब डिंपल को एक मौलाना रशीदी ने नंगी कहकर संबोधित किया था।

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की चायल सीट से विधायक पूजा पाल का मुद्दा तब गरमाया, जब सपा ने विधायक पूजा पाल को सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के चलते उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया. इस एक्शन को सपा नेता सही बता रहे हैं, तो बीजेपी ने अखिलेश को घेरना शुरू कर दिया है. बीजेपी इस प्रकरण को महिला–सुरक्षा और न्याय हुआ के रूप में पेश कर रही है. कुल मिलाकर पूजा पाल के रूप में बीजेपी को एक नया ब्रांड एंबेसडर और सपा के पीडीए का काउंटर प्लान मिल गया है. राजू पाल की हत्या के बाद सहानुभूति की जो लहर पूजा पाल के साथ बसपा से सपा की ओर शिफ्ट हुई थी, अब उसका सियासी लाभ बीजेपी भी उठाने की तैयारी में है. बीजेपी, सपा को ओबीसी विरोधी बताने में जुटी है. बीजेपी की रणनीति पूजा पाल के बहाने अखिलेश के सबसे बड़े विनिंग फॉर्मूले पीडीए की हवा निकालने की है. यूपी में पाल–बघेल जाति की पिछड़ों में अच्छी–खासी संख्या है, जो सपा के पीडीए की सियासी रीढ़ मानी जाती है. इस तरह बीजेपी अखिलेश यादव को पाल समाज का विरोधी बताने की कवायद करने में जुटी है।

शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, संघ की भी पसंद

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा अध्यक्ष वही बनेगा, जिस पर प्रधानमंत्री का भरोसा हो और जो संघ की भी पसंद हो, साथ ही संगठन व चुनाव प्रबंधन का अनुभव रखता हो।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। 'मामा' के नाम से लोकप्रिय शिवराज को आरएसएस का समर्थन प्राप्त है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी राजनीतिक अहमियत को भली–भाँति जानते हैं। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों ने उनकी दावेदारी और मजबूत कर दी है।

भाजपा को सितंबर में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। इसके लिए कई नाम चर्चा में हैं, जिनमें शिवराज सिंह चौहान सबसे प्रमुख हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा अध्यक्ष वही बनेगा, जिस पर प्रधानमंत्री का भरोसा हो और जो संघ की भी पसंद हो, साथ ही संगठन व चुनाव प्रबंधन का अनुभव रखता हो। इन सभी मानकों पर शिवराज खरे उतरते हैं। हाल ही में ग्वालियर में उनकी संघ प्रमुख मोहन भागवत से बंद कमरे में हुई मुलाकात ने अटकलों को और बल दिया है। हालांकि, भाजपा अपने अप्रत्याशित फैसलों के लिए जानी जाती है, इसलिए अंतिम नाम का खुलासा कुछ ही दिनों में होगा। ओबीसी वर्ग से आने वाले शिवराज सिंह संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। युवा मोर्चा से शुरुआत कर उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक का सफर तय किया है। उनकी छवि सरल, सहज और सर्वसुलभ नेता की है। कार्यकर्ताओं और आम जनता से उनका सीधा जुड़ाव उन्हें अन्य नेताओं से अलग करता है। मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज ने लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना जैसी योजनाओं से ग्रामीण और महिला वोटबैंक को मजबूत किया। यही कारण है कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी जनता का भरोसा हासिल है। राजनीतिक जीवन में शिवराज सिंह ने कई उतार–चढ़ाव देखे हैंकृडंपर कांड और व्यापमं जैसे आरोपों के बावजूद उनकी छवि अपेक्षाकृत साफ रही। वे 18 साल से अधिक समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कई बार सांसद चुने गए और हाल ही में केंद्रीय मंत्री बने हैं।

केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें पाँचवें नंबर पर शपथ दिलाई गई थी, जो उनके महत्व को दर्शाता है। मोदी, शाह और नड्डा के बाद अब शिवराज ही ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने अब तक भाजपा अध्यक्ष का पद नहीं संभाला है। शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक अनुभव, जनस्वीकार्य छवि और संघ के साथ करीबी संबंध उन्हें भाजपा अध्यक्ष पद के सबसे मजबूत दावेदारों में खड़ा करते हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसलाः शादी का रजिस्ट्रेशन न होने पर भी शादी रहेगी वैध

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि शादी का रजिस्ट्रेशन न होना शादी को अवैध नहीं बनाता। कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ शादी का प्रमाण प्रस्तुत करने का तरीका है, इसकी अनुपस्थिति से विवाह की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता।

यह निर्णय जस्टिस मनीष निगम ने 26 अगस्त को सुनाया। यह फैसला आजमगढ़ की फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए आया, जिसमें याचिकाकर्ता की उस अर्जी को खारिज कर दिया गया था, जिसमें शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने से छूट मांगी गई थी।

मामला सुनील दुबे और उनकी पत्नी से जुड़ा है, जिन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 13 (बी) के तहत 23 अक्टूबर 2024 को आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों को शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने का निर्देश दिया था। सुनील दुबे ने दलील दी कि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, इसलिए उन्हें प्रमाणपत्र जमा करने से छूट दी जाए। उनकी पत्नी ने भी इस अर्जी का समर्थन किया, लेकिन फैमिली कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुँचा।

जस्टिस मनीष निगम ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के तहत विधिवत संपन्न हुई शादी वैध होती है। राज्य सरकारें विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बना सकती हैं, परंतु रजिस्ट्रेशन न होने पर विवाह अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य केवल विवाह का सबूत प्रस्तुत करना है। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 8(5) के अनुसार, रजिस्ट्रेशन न होने से विवाह की वैधता पर कोई प्रश्न नहीं उठता। सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाईकोर्ट्स के फैसले भी इसी सिद्धांत को मान्यता देते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ किया कि यदि विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधानों के तहत संपन्न हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन न होने पर भी वह पूरी तरह वैध माना जाएगा।

तेजस्वी राहुल को पीएम बनाने को तैयार लेकिन...

यात्र में मजा आना जरूरी है, जैसा कि राहुल खुद कहते हैं, और लगता है कि उन्हें तेजस्वी यादव के साथ यह सफर खूब रास आ रहा है।

अजय कुमार
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा इन दिनों बिहार की सड़कों पर धूम मचा रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही राहुल गांधी यहां भी पूरे जोश के साथ डटे हुए हैं। यात्रा में मजा आना जरूरी है, जैसा कि राहुल खुद कहते हैं, और लगता है कि उन्हें तेजस्वी यादव के साथ यह सफर खूब रास आ रहा है। लेकिन इस मजेदार सफर के बीच एक सवाल बार–बार उछल रहा है– क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानने से कतरा रहे हैं? तेजस्वी तो राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की बात खुलकर कर रहे हैं, लेकिन राहुल की तरफ से वैसी ही निष्ठा क्यों नहीं दिख रही? यह सवाल बिहार की राजनीति में तूफान खड़ा कर रहा है, खासकर जब 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। यात्रा की शुरुआत सासाराम से हुई, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है, और इसे श्एसआईआरश (सिस्टेमेटिक इलेक्टोरल रोल) का नाम देकर संस्थागत चोरी कर रहा है। यहां तक कि छोटे बच्चे भी श्वोट चोर, गद्दी छोड़श का नारा लगा रहे हैं, जैसा कि राहुल ने खुद बताया। यात्रा में बुलेट बाइक पर सवार होकर दोनों नेता जनता के बीच पहुंचे, जो एक आकर्षक दृश्य था। लेकिन इसी दौरान कुछ हादसे भी हुए, काफिले की गाड़ियों से दो सुरक्षा जवानों को चोट लगी, और एक युवक ने अचानक राहुल को किस कर लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया, और सवाल उठा कि आगे कौन लीड कर रहा है, राहुल या तेजस्वी?

तेजस्वी यादव राहुल को श्बड़े भाईश कहकर संबोधित कर रहे हैं, और उनकी हर बात में सम्मान झलकता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चिराग पासवान पर सवाल उठा, तो तेजस्वी ने उन्हें श्बड़े भाईश बताते हुए शादी करने की सलाह दी। राहुल हंस पड़े और बोले, श्यह मेरे लिए भी लागू होता है।श तेजस्वी ने तुरंत जवाब दिया कि पापा (लालू यादव) ने आपको यह सलाह पहले ही दे दी है। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव से पहले

पटना की इंडिया ब्लॉक मीटिंग में लालू यादव ने राहुल से कहा था, श्आप दूल्हा बनिए, हम बाराती बनने को तैयार हैं।श अब तेजस्वी भी यही बात दोहरा रहे हैं कि राहुल देश के प्रधानमंत्री बनें। लेकिन राहुल तेजस्वी को बिहार का सीएम फेस घोषित करने से क्यों बच रहे हैं?

यह सवाल मीडिया ने राहुल से कई बार पूछा। अररिया में एक संवाददाता सम्मेलन में जब पूछा गया कि तेजस्वी आपको पीएम बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तेजस्वी को सीएम फेस क्यों नहीं मान रही? राहुल ने जवाब दिया, श्हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, कोई टेंशन नहीं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, हम एक–दूसरे की मदद कर रहे हैं, मजा आ रहा है। राजनीतिक और वैचारिक रूप से हम जुड़े हुए हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा।श लेकिन सीधा जवाब नहीं दिया। बिहार कांग्रेस के नेता जैसे कृष्णा अल्लावरु या राजेश कुमार भी यही सवाल टालते रहे हैं। वे कहते हैं कि यह फैसला आरजेडी का है, या फिर तेजस्वी चुनाव अभियान समिति के प्रमुख हैं। लेकिन सच्चाई यह लगती है कि कांग्रेस की हरी झंडी का इंतजार है।

क्या राहुल को तेजस्वी पर भरोसा नहीं? तेजस्वी तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वे राहुल को बड़े भाई बताते हैं, उनके साथ बाइक चलाते हैं, और पीएम बनाने का ऐलान करते हैं। लेकिन राहुल का रुख श्फूफाश जैसा क्यों लग रहा है? आजकल सोशल मीडिया पर फूफा की नाराजगी के रील्स खूब चलते हैं, जहां फूफा शादी में रूठ जाते हैं। यहां भी राहुल को श्दूल्हाश बनने की सलाह दी जा रही है, लेकिन वे तेजस्वी को श्दूल्हाश बनाने से कतरा रहे हैं। लालू यादव ने नीतीश कुमार को भी पीएम बनाने पर हामी भरी थी, लेकिन वह सिर्फ दिखावा था, क्योंकि वे नीतीश को सीएम भी नहीं रहने देना चाहते थे। लेकिन तेजस्वी के मामले में राहुल का डर क्या है? तेजस्वी तो ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल की तरह चुनौती नहीं दे रहे। बिहार की राजनीति में महागठबंधन की एकता जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने 4 सीटें जीतीं, कांग्रेस ने 3। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी 71 सीटों के साथ। लेकिन कांग्रेस जूनियर पार्टनर की भूमिका से बाहर निकलना चाहती है। राहुल की बिहार यात्राएं दलितों और युवाओं पर फोकस कर रही हैं, जो आरजेडी के वोट बैंक को प्रभावित कर सकती हैं। कांग्रेस को लगता है कि आरजेडी की जाति–आधारित राजनीति से अलग, वे रोजगार, शिक्षा और सेकुलरिज्म पर लड़ेंगी। लेकिन इससे आरजेडी चिंतित है। वाम दल भी चुप हैं, लेकिन वे तेजस्वी को सीएम मानने में कोई दिक्कत नहीं देखते।

यात्रा में उत्साह है। औरंगाबाद में दोनों नेताओं ने सूर्य मंदिर में पूजा की, जहां महिलाएं श्वोट चोर गद्दी छोड़श का नारा लगा रही थीं। पूर्णिया में बाइक रैली ने जनता को आकर्षित किया। लेकिन पप्पू यादव जैसे नेता तेजस्वी को श्अहंकारी युवराजश कहकर हमला कर रहे हैं। एक रैली में पप्पू यादव को मंच से नीचे धकेला गया था, जब राहुल मौजूद थे। यह दिखाता है कि महागठबंधन में आंतरिक कलह है। तेज प्रताप यादव भी अलग जन संवाद कर रहे हैं, जो तेजस्वी के लिए चुनौती बन सकता है। भाजपा इस पर चुटकी ले रही है। वे कहते हैं कि राहुल का अहंकार दिख रहा है, जो सीएम फेस पर सवाल टाल रहे हैं। नीतीश कुमार और मोदी पर हमले हो रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की एकता पर सवाल हैं। राहुल की न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से प्रेरित यह यात्रा वोटर अधिकारों पर फोकस है, लेकिन इसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा छिपी है। क्या राहुल बिहार में कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, या तेजस्वी को सीएम बनने से रोक रहे हैं? लालू का सोनिया गांधी को समर्थन वैसा ही था, जैसा अब तेजस्वी का है। लेकिन राहुल का रुख अलग है। अगर महागठबंधन जीतता है, तो सीएम कौन बनेगा? तेजस्वी की मेहनत और राहुल की लोकप्रियता मिलकर नीतीश को चुनौती दे सकती है। लेकिन भरोसे की कमी से हार भी हो सकती है। यात्रा में मजा आ रहा है, लेकिन सवाल बाकी हैं, क्या राहुल तेजस्वी को श्दूल्हाश बनने देंगे, या फूफा बनकर रूठे रहेंगे? बिहार की जनता देख रही है, और चुनाव बताएंगे कि यह पार्टनरशिप कितनी मजबूत है।

यह यात्रा सिर्फ वोटर अधिकारों की नहीं, बल्कि नेतृत्व की जंग भी है। राहुल की पिछली यात्राओं में तन्मयता दिखी, लेकिन यहां तेजस्वी के साथ समानता क्यों नहीं? तेजस्वी ने कहा कि राहुल पीएम बनेंगे, अगर इंडिया ब्लॉक सत्ता में आया। लेकिन बिहार में कांग्रेस का चुप रहना संदेह पैदा करता है। क्या कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही है? या राहुल को तेजस्वी की छवि पर शक है? लालू की पुरानी बातें याद आती हैं, जब उन्होंने नीतीश को श्जहर पीकरश सीएम बनाया था। लेकिन अब मकसद तेजस्वी को सीएम बनाना है, और राहुल रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकते, क्योंकि वे खुद बिहार के सीएम नहीं बनने वाले।

सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है। लोग कहते हैं कि राहुल की यात्रा महागठबंधन को मजबूत कर रही है, लेकिन कुछ इसे राहुल का हाईजैक मानते हैं। तेजस्वी की तरफ से पूरा समर्थन है, लेकिन राहुल वैसा क्यों नहीं कर रहे? क्या यह रणनीति है, या भरोसे की कमी? चुनाव नजदीक हैं, और यह सवाल जवाब मांग रहे हैं। महागठबंधन की एकता पर निर्भर करेगा बिहार का भविष्य। राहुल और तेजस्वी का यह सफर मजेदार है, लेकिन राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण भी। जनता की नजरें टिकी हैं कि क्या यह जोड़ी नीतीश–मोदी को हरा पाएगी, या

मॉनसून में मच्छरों से हो सकता है डेंगू मलेरिया, बचाव के लिए तुरंत करें ये उपाय

इन दिनों मानसून में कई राज्यों में बाढ़ से हालात खराब हैं. इस मौसम में मच्छर जनित रोगों जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि का खतरा काफी बढ़ जाता है.

इस बार मानसून में हर जगह हालात बेहद ही खराब होते जा रहे हैं. देश के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति बन गई है. गली–गली पानी भरने से आम जीवन अस्त–व्यस्त है. बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा मच्छर जनित रोगों जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया के होने का खतरा भी बहुत अधिक बढ़ जाता है. जमा हुआ पानी मच्छरों को पनपने का भरपूर मौका देता है. ऐसे में आपके घर के आसपास भी पानी इकट्ठा है तो आप घर से मच्छरों को दूर रखने के लिए ये उपाय आजमाना शुरू कर दें. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एक बार डेंगू, चिकनगुनिया हो जाए और इसका इलाज सही से ना मिले तो इसमें जान भी चली जाती है.

मच्छरों से बचने के उपाय

पानी जमा न होने दें

- सबसे पहले आप अपने घर या उसके आसपास जमा हुआ पानी हटाने की कोशिश करें. ये मच्छरों को पनपने का भरपूर मौका देता है.
- मच्छर रुके हुए पानी में पनपते हैं, इसलिए पहला कदम है कि अपने घर के आसपास पानी जमा होने वाले स्थानों को सबसे पहले हटाएं.
- गमलों की तश्तरियां, बाल्टियां और बर्डबाथ नियमित रूप से खाली करें.
- पानी रखने वाले बर्तनों को अच्छी तरह से ढककर रखें.
- कूलर, पानी की टंकी और नालियों को कम से कम हफ्ते में एक बार साफ करें.

दरवाजे–खिड़कियों को मच्छर–रोधी बनाएं

- खिड़कियों और दरवाजों पर यदि जाली नहीं लगी है तो जरूर लगवा लें.
- शाम होने से पहले सभी खिड़कियां बंद कर लें. इससे मच्छर अंदर नहीं घुसेंगे.
- जाली में कोई छेद या खाली जगह न हो. दरवाजों पर क्लोजर लगाएं.

नेचुरल रेपेलेंट्स का करें इस्तेमाल

मच्छरों को दूर रखने के लिए आप घर के अंदर रेपेलेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं:

- नेचुरल तरीकों में नीम का तेल, सिट्रोनेला मोमबत्तियां, कपूर और तुलसी के पौधे प्राकृतिक रूप से मच्छरों को भगाने में मदद करते हैं.
- आप चाहें तो मार्केट में मिलने वाले केमिकल युक्त रेपेलेंट्स जैसे लिक्विड वेपोराइजर, कॉइल और प्लग–इन मशीनें भी खरीद सकते हैं. इनसे भी मच्छर मरते हैं.
- इन्हें प्रॉपर वेंटिलेशन वाली जगह पर ही रखकर ऑन करें, ताकि इसका केमिकल युक्त धुआं निकलता भी रहे.

घर को साफ रखें

- गंदगी और नमी वाले स्थान मच्छरों को आकर्षित करते हैं. अपने घर को सूखा और हवादार रखें.
- दिन के समय आप खिड़कियां थोड़ी खोल सकते हैं.
- बिस्तर की चादर और पर्दे को बदलते रहें.
- गीले कपड़े घर के अंदर टंगे न छोड़ें।
- कूड़े को ढककर रखें और हर दिन बाहर फेंकें.
- मच्छर अधिक हैं तो मच्छरदानी लगाकर सोएं.
- शाम के समय आप और बच्चों को फुल–स्लीव्स के कपड़े पहनाएं.
- हल्के रंग के कपड़े पहनने से भी मच्छर कम काटते हैं।

डब्ल्यूएचओ ने हेपेटाइटिस-डी को माना कैंसर का कारण, जानिए इससे बचने के उपाय

हेपेटाइटिस डी एक लीवर संक्रमण है जो हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस (HDV) के कारण होता है और वायरल हेपेटाइटिस का सबसे गंभीर रूप माना जाता है. यह संक्रमण केवल उन लोगों को हो सकता है जिन्हें पहले से हेपेटाइटिस बी का संक्रमण है।

हेपेटाइटिस–डी लिवर से जुड़ा एक गंभीर संक्रमण है, जो हेपेटाइटिस डी वायरस (एचडीवी) के कारण होता है। यह वायरस केवल उन्हीं लोगों को संक्रमित करता है, जो पहले से हेपेटाइटिस बी वायरस (एचबीवी) से संक्रमित होते हैं।

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इसे कैंसर का प्रमुख कारण घोषित किया है।

क्यों चर्चा में है हेपेटाइटिस-डी?

हाल के दिनों में हेपेटाइटिस की चर्चा तेज हो गई है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान हेपेटाइटिस–डी पर है क्योंकि डब्ल्यूएचओ की अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी ने इसे कैंसरकारी घोषित कर दिया है। यह स्थिति लिवर में सूजन से जुड़ी होती है। पहले हेपेटाइटिस–ए, बी और सी को गंभीर माना जाता था, लेकिन अब डी प्रकार भी खतरनाक रूप में सामने आ रहा है।

एचडीवी वायरस अपने आप शरीर में नहीं फैलता, बल्कि इसे एचबीवी की मदद चाहिए होती है। अब तक इस पर कम चर्चा होती थी, लेकिन हालिया रिपोर्टों ने इसे सुर्खियों में ला दिया है।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, "हर 30 सेकंड में दुनिया में एक व्यक्ति लिवर से जुड़ी गंभीर बीमारी या लिवर कैंसर से मर रहा है।" आईएआरसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि हेपेटाइटिस डी, अकेले बी वायरस की तुलना में लिवर कैंसर के जोखिम को 2 से 6 गुना तक बढ़ा सकता है। इसलिए इसकी स्क्रीनिंग और समय पर उपचार बेहद आवश्यक है।

हेपेटाइटिस क्या है?

हेपेटाइटिस एक वायरल संक्रमण है, जो मुख्यतः लिवर को प्रभावित करता है। इसके पांच प्रकार हैं कृ ए, बी, सी, डी और ई:

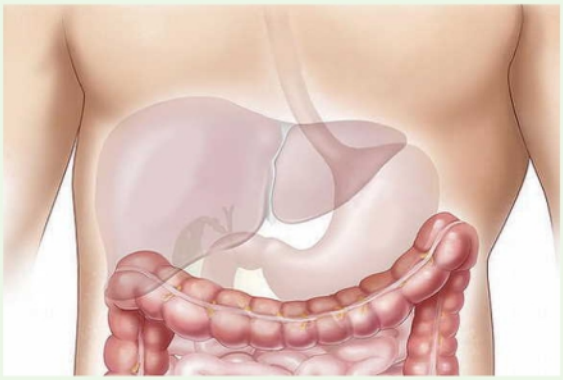

- ए और ई दूषित भोजन व पानी से फैलते हैं।
- बी, सी और डी संक्रमित खून या शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से फैलते हैं।

डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि दुनियाभर में 4.8 करोड़ लोग हेपेटाइटिस–डी से संक्रमित हैं। यदि यह एचबीवी के साथ हो, तो मृत्यु दर अन्य प्रकार की तुलना में 20ः अधिक हो जाती है।

संक्रमण कैसे फैलता है?

एचडीवी संक्रमण कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक रह सकता है। यह निम्न तरीकों से फैल सकता हैः

- संक्रमित रक्त या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क से
- असुरक्षित यौन संबंध
- संक्रमित सुइयों का उपयोग
- प्रसव के दौरान मां से शिशु में संक्रमण

'जर्नल ऑफ हेप्टालॉजी' में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, एचडीवी संक्रमण लिवर कैंसर का खतरा लगभग दोगुना कर देता है। इससे होने वाले लक्षणों में शामिल हैंः

- थकान
- पेट दर्द
- पीलिया
- भूख की कमी
- उल्टी और बुखार

एक शोध के अनुसार, क्रोनिक हेपेटाइटिस बीध्डी से संक्रमित 70ः लोगों को लिवर स्कैरिंग (फाइब्रोसिस) की समस्या हो सकती है, जिसे विकसित होने में 10 साल तक लग सकते हैं।

हेपेटाइटिस-डी से बचाव कैसे करें?

एचडीवी का कोई विशिष्ट टीका नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाकर आप दोनों संक्रमणों से बच सकते हैं। बचाव के लिए इन बातों का ध्यान रखें:

- संक्रमित रक्त या तरल पदार्थ के संपर्क से बचें।
- इंजेक्शन या सुइयों को साझा न करें।
- व्यक्तिगत वस्तुएं जैसे रेजर, टूथब्रश आदि साझा न करें।
- यौन संबंध के दौरान सुरक्षा का पालन करें।
- हेपेटाइटिस बी का इलाज डॉक्टर की सलाह से पूरा करें।

हेपेटाइटिस–डी एक गंभीर बीमारी है जो अब कैंसर का कारण मानी जा रही है। इसके खतरे को कम करने के लिए जागरूकता, सावधानी और समय पर इलाज बेहद जरूरी है।

नोट– संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

मखाना के सहारे सीमांचल में वोट की फसल काटने उतरे राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कटिहार जिले के मखाना खेतों में उतरकर किसानों की दुर्दशा को जोर-शोर से उठाया।

अजय कुमार
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

बिहार की सियासत में इन दिनों मखाना किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ है। यह फसल, जिसे बिहार का गौरव कहा जाता है, अब राजनीतिक दलों के लिए वोट का हथियार बन चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कटिहार जिले के मखाना खेतों में उतरकर किसानों की दुर्दशा को जोर–शोर से उठाया।

23 अगस्त 2025 को घुटनों तक पानी में खड़े होकर उन्होंने मखाना किसानों के साथ न सिर्फ उनकी मेहनत को देखा, बल्कि उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश भी की। सोशल मीडिया पर साझा किए गए उनके वीडियो और बयानों ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। राहुल ने कहा कि बिहार दुनिया का 90 प्रतिशत मखाना पैदा करता है, लेकिन मेहनत करने वाले किसान और मजदूर, जो ज्यादातर दलित और अति पिछड़े समुदायों से हैं, मुनाफे का सिर्फ एक प्रतिशत ही कमा पाते हैं। बाजार में मखाना 1000 से 2000 रुपये प्रति किलो बिकता है, लेकिन किसानों को नाममात्र कीमत मिलती है, और सारा लाभ बिचौलियों की जेब में चला जाता है।

राहुल ने बिहार की एनडीए सरकार और केंद्र की सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने वादा किया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो मखाना किसानों को बिचौलियों से मुक्त कर उनकी उपज को सीधे बाजार तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान उनके साथ विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी भी थे, जो मल्लाह समुदाय से आते हैं और खुद को इस समुदाय का बेटा कहते हैं। सहनी की मौजूदगी ने इस यात्रा को और भी राजनीतिक रंग दिया, क्योंकि मल्लाह समुदाय बिहार की सियासत में अहम भूमिका निभाता है। यह समुदाय मखाना उत्पादन वाले क्षेत्रों में प्रभावशाली है और अन्य पिछड़े वर्गों को अपने साथ जोड़ने की ताकत रखता है। सहनी, जो कभी एनडीए के साथ थे और अब महागठबंधन का हिस्सा हैं, 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका की उम्मीद कर रहे हैं। चर्चा है कि वे 60 सीटों की मांग कर रहे हैं और डिप्टी सीएम पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो सियासी पाला बदलने की संभावना भी बनी हुई है।

राहुल गांधी का मखाना किसानों की दुर्दशा पर बोलना और बिचौलियों को दोष देना सियासी तौर पर तो आकर्षक है, लेकिन इसमें एक विरोधाभास भी दिखता है। देश के सभी किसान बिचौलियों की मार झेलते हैं, और इस

समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार 2020 में तीन कृषि कानून लेकर आई थी। इन कानूनों का मकसद था कि किसान अपनी उपज को मंडियों के बाहर सीधे खरीदारों, जैसे निजी कंपनियों या रिटेलरों को बेच सकें। इससे बिचौलियों की भूमिका कम हो सकती थी, और मखाना जैसे उत्पादों को किसान बेहतर कीमत पर बेच सकते थे। लेकिन कांग्रेस ने इन कानूनों का जमकर विरोध किया था। उस वक्त राहुल ने कहा था कि मंडियों का कमजोर होना छोटे किसानों को नुकसान पहुंचाएगा। अब वही राहुल मखाना किसानों की कम कीमत की शिकायत को बिचौलियों से जोड़ रहे हैं। यह सवाल उठता है कि अगर बिचौलियों से मुक्ति की बात वे आज कर रहे हैं, तो कृषि कानूनों का विरोध क्यों किया? यह विरोधाभास उनकी बातों को सियासी रंग देता है। मखाना किसानों की शिकायत है कि उनकी उपज 400–750 रुपये प्रति क्विंटल खरीदी जाती है, जबकि बाजार में यह 900–1600 रुपये प्रति क्विंटल बिकती है। अगर किसानों को सीधे बाजार तक पहुंच मिले, तो उनकी आय बढ़ सकती है।

मखाना किसानों की समस्याएं सिर्फ बिचौलियों तक सीमित नहीं हैं। यह फसल बिहार के मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्रों में उगाई जाती है, जो 100 से अधिक विधानसभा सीटों को प्रभावित करती है। मखाना की खेती बेहद मेहनत भरी है। पानी में डूबकर काले खोल वाले बीज निकालने से लेकर सुखाने, भूनने और पैकेजिंग तक का काम श्रमसाध्य है। किसान आज भी पुरानी तकनीकों पर निर्भर हैं। आधुनिक मशीनरी, पर्याप्त ऋण, और फसल बीमा की कमी उनकी परेशानियों को बढ़ाती है। सरकार ने मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यह बोर्ड मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने का वादा करता है। लेकिन इसकी स्थापना में देरी हो रही है, और जमीनी स्तर पर बदलाव अभी नजर नहीं आ रहा। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, जैसे 'सुवर्ण वैदेही', उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे प्रति हेक्टेयर 16 से 28 क्विंटल तक

23 अगस्त 2025 को घुटनों तक पानी में खड़े होकर उन्होंने मखाना किसानों के साथ न सिर्फ उनकी मेहनत को देखा, बल्कि उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश भी की। सोशल मीडिया पर साझा किए गए उनके वीडियो और बयानों ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी।

उत्पादन हो रहा है। साथ ही, मखाना विकास योजना के तहत 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है, जिसका अधिकतम लाभ 72,750 रुपये प्रति हेक्टेयर है। लेकिन इन योजनाओं का असर अभी पूरी तरह दिखना बाकी है।

मखाना बिहार की सियासत में अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। यह फसल 36,727 हेक्टेयर में उगाई जाती है और 56,400 टन उत्पादन देती है। इसे मुख्य रूप से मल्लाह और अति पिछड़े समुदाय उगाते हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। एनडीए इसे वैश्विक सुपरफूड के रूप में प्रचारित कर रही है। मखाना को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, जैसे विदेशी मेहमानों को मखाना भेंट करना। मखाना बोर्ड को मिथिलांचल और सीमांचल के 72 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए की स्थिति मजबूत करने का रणनीतिक कदम माना जा रहा है। लेकिन बोर्ड की स्थापना में देरी से किसानों में असंतोष है। कुछ नेताओं ने बोर्ड को सीमांचल में स्थापित करने की मांग उठाई है, जिसे सत्ताधारी दल ने सियासी नौटंकी करार दिया। यह विवाद दिखाता है कि मखाना अब सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सियासी मुद्दा भी है।

राहुल गांधी का मखाना किसानों पर दांव सियासी रणनीति का हिस्सा है। वे मखाना बोर्ड की प्रगति पर सवाल उठाकर सरकार को घेर रहे हैं। उनकी कोशिश सीमांचल और मिथिलांचल के मुस्लिम और पिछड़े समुदायों के वोट साधने की है। खासकर सीमांचल, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां कांग्रेस अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। मल्लाह समुदाय इस खेल में अहम कड़ी है। यह समुदाय न सिर्फ मखाना उत्पादन में सक्रिय है, बल्कि सियासी तौर पर भी जागरूक है। परंपरागत रूप से यह समाजवादी दलों के साथ रहा है, लेकिन अब सहनी जैसे नेता इसे महागठबंधन की ओर ले जा रहे हैं। सहनी की पार्टी 2020 में एनडीए के साथ थी और तीन सीटें जीती थीं, बाद में उनके विधायक सत्ताधारी दल में चले गए। अब सहनी महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा सियासी गणित उन्हें फिर से पाला बदलने के प्रेरित कर सकती है।

मखाना किसानों का मुद्दा बिहार की सियासत में नया रंग भर रहा है। यह सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। राहुल गांधी की यात्रा और एनडीए की योजनाएं, दोनों ही किसानों के नाम पर वोट की खेती कर रही हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या किसानों की स्थिति में वास्तविक बदलाव आएगा? आधुनिक तकनीक, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और बाजार तक सीधी पहुंच से ही मखाना किसानों की जिंदगी बदल सकती है। बिहार का मखाना दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है, बशर्ते सियासत से परे ठोस कदम उठें। उम्मीद है कि 2025 का चुनाव इस दिशा में कुछ नया लाएगा, और मखाना किसान अपनी मेहनत का सही फल पा सकेंगे।

योगी के तेवर ढीले पड़ते ही स्कूल-कॉलेजों के आसपास फिर मंडराने लगे रोमियों

एंटी-रोमियो स्क्वॉड की शुरुआत 2017 में हुई थी, जब योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इन दुष्टों पर नकेल कसी थी। लेकिन अब, 2025 में, जैसे ही सरकार के तेवर थोड़े ढीले पड़े, स्कूल और कॉलेजों के बाहर मनचले फिर मंडराने लगे हैं।

संजय सक्सेना
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालते के बाद उनके सख्त तेवरों से रोमियों (मनचलों) की शामत आ गई थी, लेकिन योगी के तेवर ढीले पड़ते ही यूपी में फिर वही पुरानी बीमारी लौट आई है। एंटी–रोमियो स्क्वॉड की शुरुआत 2017 में हुई थी, जब योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इन दुष्टों पर नकेल कसी थी। लेकिन अब, 2025 में, जैसे ही सरकार के तेवर थोड़े ढीले पड़े, स्कूल और कॉलेजों के बाहर मनचले फिर मंडराने लगे हैं। पुलिस की गश्त गायब है, और स्कूल–कॉलेज जाती लड़कियां रोजाना छेड़छाड़ का शिकार हो रही हैं। यह न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि एक खुली चुनौती है उस सिस्टम को जो महिलाओं की इज्जत की रक्षा करने का दावा करता है।

इन रोमियो बनने वाले गुंडों को अब सख्त सबक सिखाने का वक्त आ गया है, नहीं तो यह समाज की बेटियों को और कितना सहन करवाएगा?

कल्पना कीजिए, जब एक 16 साल की स्कूली लड़की, किताबें थामे घर से निकलती है, तो वह कितनी सहमी रहती होगी। क्योंकि रास्ते में अथवा स्कूल गेट के बाहर, कॉलेज कैंपस के पास हर जगह उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले मनचले घात लगाए स्कूटी पर बैठे या गुट बनाकर खड़े नजर आ जाते हैं। फब्तियां कसना, सीटी मारना, पीछा करना, या हाथ लगाने की कोशिश, ये सब अब रोजमर्रा की बात हो गई है। जुलाई 2025 में ऊन्नाव जिले में एक स्कूली लड़की ने तंग आकर खुद ही

आरोपी को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ जड़ दिए।

वीडियो वायरल हुआ, लेकिन क्या इससे समस्या हल हो गई? नहीं, यह तो सिर्फ एक उदाहरण है कि बेटियां अब खुद अपनी रक्षा करने को मजबूर हैं, क्योंकि पुलिस कहां है? 2023 में अंबेडकर नगर में एक साइकिल चलाती लड़की की छेड़छाड़ के कारण मौत हो गई थी, लेकिन 2025 में भी स्थिति जस की तस है। ये मनचले कौन हैं? ये वही कमजोर दिमाग वाले कायर हैं, जो महिलाओं को कमजोर समझकर अपनी मर्दानगी दिखाते हैं। लेकिन हकीकत में ये समाज के कीड़े हैं, जो बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं।

एंटी-रोमियो स्क्वॉड का क्या हुआ

2017 से 2025 तक इस स्क्वॉड ने 1.4 करोड़ लोगों को चेतावनी दी, 32,077 पर चालान काटे और केस दर्ज किए। मार्च 2025 में डीजीपी ने बताया कि 24,000 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। अगस्त 2024 में स्क्वॉड को फिर से एक्टिवेट करने के आदेश दिए गए थे, मुख्यमंत्री योगी ने महिलाओं की सुरक्षा पर जोर दिया था।

मई 2025 में लखनऊ में इसे श्महिला सुरक्षा टीमश नाम दिया गया। फिर भी जमीनी हकीकत अलग है। फरवरी 2025 में रिपोर्ट्स आईं कि 2022 चुनावों से पहले आलोचना के कारण स्क्वॉड को स्केल बैक कर दिया गया था। अब पुलिस स्कूल–कॉलेजों के बाहर नजर नहीं आती। मनचले बेखौफ हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सजा का डर कम हो गया है। यह ढीलापन नहीं, अपराध को बढ़ावा देना है!

ये रोमियो बनने वाले शैतान सिर्फ छेड़छाड़ नहीं करते, वे महिलाओं की आजादी छीनते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 90 प्रतिशत महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर छेड़छाड़ का शिकार होती हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां बेटियां शिक्षा के लिए संघर्ष कर रही हैं, ये घटनाएं उन्हें घर बैठाने पर मजबूर कर देती हैं। याद कीजिए 2017 को, जब एंटी–रोमियो स्क्वॉड ने शुरुआत की थी, तब मनचलों में खौफ था। लेकिन अब ये स्क्वॉड मोरल पुलिसिंग में बदल गए, कभी प्राइवेसी का उल्लंघन करने लगे, लेकिन मूल मकसद तो महिलाओं की सुरक्षा था। आज जरूरत है सख्ती की, न कि नाम बदलने की। लखनऊ से लेकर उन्नाव तक, हर जिले में पुलिस को 24•7 गश्त करनी चाहिए। इन मनचलों को पकड़कर ऐसी सजा दो कि वे जिंदगी भर याद रखें। कानून तो है, आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा भंग करना), लेकिन अमल कहां?

सोचिए, एक कॉलेज स्टूडेंट रोजाना घर से निकलती है, लेकिन मन में डर रहता है? क्या आज सुरक्षित पहुंचूंगी? ये डर इन रोमियो की वजह से है, जो खुद को हीरो समझते हैं लेकिन असल में विलेन हैं। समाज को इनसे घृणा करनी चाहिए।

माता–पिता, शिक्षक, और युवा सबको मिलकर इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। सरकार से मांग है वह एंटी–रोमियो स्क्वॉड को फिर से पूरी तरह से एक्टिव करे, पुलिस को ट्रेनिंग दी जाये और स्कूल कॉलेजों के बाहर और आसपास सीसीटीवी लगाये जायें। ये मनचले समाज के दुश्मन हैं, इन्हें कुचलना जरूरी तो इन दुष्टों को बख्शना अपराध है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने अधिकारियों के पेंच कसना होगा, वह फिर से सख्त तेवर दिखाएंगे तभी हमारी बच्चियों को घर के बाहर सुरक्षा मिलेगी, नहीं तो ये रोमियो राज्य को बदनाम कर देंगे। महिलाओं की सुरक्षा कोई चुनावी वादा नहीं, बुनियादी हक है। आखिर कब तक बेटियां सहेंगी? अब वक्त है आक्रमक कार्रवाई का, इन रोमियो को जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है!

भारत ने नहीं झुकाया सिर ट्रंप की धमकी को दिया आंकड़ों से करारा जवाब

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत को बार-बार टैरिफ और जुर्माने की धमकियां दे रहे हैं, खासकर रूस से तेल और हथियारों के व्यापार को लेकर। लेकिन भारत ने न केवल इन धमकियों को नजरअंदाज किया, बल्कि अमेरिका और यूरोपीय संघ की दोहरी नीतियों को उजागर कर जवाबी रुख अपनाया है।

अजय कुमार
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

डोनाल्ड ट्रंप की भारत के प्रति बढ़ती चिढ़ और अमेरिका की दोहरी नीति ने वैश्विक मंच पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत को बार–बार टैरिफ और जुर्माने की धमकियां दे रहे हैं, खासकर रूस से तेल और हथियारों के व्यापार को लेकर। लेकिन भारत ने न केवल इन धमकियों को नजरअंदाज किया, बल्कि अमेरिका और यूरोपीय संघ की दोहरी नीतियों को उजागर कर जवाबी रुख अपनाया है। भारत का स्पष्ट कहना है कि जब अमेरिका और यूरोप स्वयं रूस से भारी मात्रा में सामान आयात कर रहे हैं, तो भारत पर रूस के साथ व्यापार को लेकर उंगली उठाना अनुचित और अतार्किक है। यह स्थिति वैश्विक भू–राजनीति में दोहरे मानदंडों को उजागर करती है, जहां अमेरिका भारत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद अपनी जरूरतों के लिए रूस से व्यापार जारी रखे हुए है।

ट्रंप की बयानबाजी में एक साफ विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ वह भारत को ष्महान मित्रष् और ष्महान देशष् कहते हैं, दूसरी तरफ 25: रेसिप्रोकल टैरिफ और रूस से व्यापार के लिए जुर्माने की धमकी देते हैं। उनकी हताशा का कारण यह है कि भारत उनके दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप को लगता है कि जिस भारत को कभी अमेरिका सड़ा हुआ गेहूं भेजता था, वह आज उनकी धमकियों का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता। उनकी चिढ़ का अंदाजा उनके बयानों से लगाया जा सकता है। कभी वह भारत की अर्थव्यवस्था को ष्मृतप्रायष् कहते हैं, तो कभी पाकिस्तान के साथ तेल सौदों की बात कर भारत को अपमानित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के पास तेल है ही नहीं, और ट्रंप का यह बयान उनकी हताशा

ट्रंप की बयानबाजी में एक साफ विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ वह भारत को महान मित्र और महान देश कहते हैं, दूसरी तरफ २५ प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ और रूस से व्यापार के लिए जुर्माने की धमकी देते हैं। उनकी हताशा का कारण यह है कि भारत उनके दबाव में झुकने को तैयार नहीं है।

का प्रतीक है। वह भारत को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत की रणनीतिक और आर्थिक ताकत के सामने उनकी एक नहीं चल रही।

भारत ने ट्रंप की धमकियों का जवाब न केवल कूटनीतिक रूप से दिया, बल्कि तथ्यों के साथ अमेरिका को आइना भी दिखाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि भारत पर रूस से तेल आयात को लेकर की जा रही आलोचना बेबुनियाद है। भारत ने बताया कि अमेरिका स्वयं रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम, खाद, और रसायन जैसे सामान आयात करता है, जो उसकी परमाणु, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, और कृषि उद्योगों के लिए जरूरी हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से मई 2025 तक अमेरिका ने रूस से 2.1 बिलियन डॉलर का आयात किया, जो पिछले साल की तुलना में 23ः अधिक है। इसमें पैलेडियम (37ः), यूरेनियम (28ः), और उर्वरक (21ः) का आयात प्रमुख है। यह आंकड़े साफ बताते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस के साथ व्यापार जारी रखा है। 2021 में अमेरिका ने रूस से 17 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात किया था, और 2024 में भी उसने उर्वरक (1.1 बिलियन डॉलर), पैलेडियम (878 मिलियन डॉलर), और यूरेनियम (624 मिलियन डॉलर) जैसे सामानों का आयात किया।

यूरोपीय संघ भी इस मामले में पीछे नहीं है। वह भारत को रूस से तेल आयात न करने की सलाह देता है, लेकिन स्वयं रूस से ईंधन, लोहा, स्टील, रसायन, और उर्वरक जैसे सामान आयात करता है। 2024 में यूरोपीय संघ ने रूस से 35.9 अरब यूरो का आयात किया, जिसमें 22.3 अरब यूरो का ईंधन प्रमुख था। यह राशि भारतीय रुपये में 3617 करोड़ से अधिक है। भारत का तर्क है कि जब अमेरिका और यूरोप अपनी जरूरतों के लिए रूस से व्यापार कर रहे हैं, तो भारत पर दबाव डालना दोहरा मापदंड है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से 35–40ः तेल आयात करता है, जो आर्थिक रूप से फायदेमंद है।

भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक ताकत ट्रंप की चिढ़ का प्रमुख कारण है। भारत ने न केवल रूस के साथ व्यापार जारी रखा, बल्कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (ठज।) पर जोर दिया, जो दोनों देशों के हितों को संतुलित करे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत जवाबी टैरिफ के बजाय बातचीत से समाधान चाहता है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी स्पष्ट किया कि भारत ट्रंप के दबाव के बावजूद अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखेगा।

भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (थ्म्व्) के डीजी अजय सहाय के अनुसार, 25ः टैरिफ से भारत की जीडीपी पर 0.2–0.5ः का असर हो सकता है, लेकिन 6ः से अधिक की विकास दर इसे संभाल सकती है। भारत वैकल्पिक बाजारों जैसे यूरोप, दक्षिण–पूर्व एशिया, और चीन की ओर भी रुख कर रहा है। चीनी राजदूत शू फेइहोंग ने भारत से आयात बढ़ाने

और व्यापार घाटा कम करने की बात कही, जो भारत के लिए एक बड़ा अवसर है।

ट्रंप की ष्अमेरिका फर्स्टष और ष्मेक इन अमेरिकाष नीतियां भारत के बिना पूरी तरह सफल नहीं हो सकतीं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार और विनिर्माण केंद्र है। अमेरिकी कंपनियां जैसे एपल, टेस्ला, और बोइंग भारत में निवेश और उत्पादन बढ़ा रही हैं। ट्रंप के प्रस्तावित 25ः टैरिफ से भारत में बने उत्पाद महंगे होंगे, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा। साथ ही, मेक इन अमेरिका की लागत बढ़ने से अमेरिकी उत्पाद वैश्विक बाजार में चीन से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। अमेरिका को यह भी डर है कि भारत यूरोप, चीन, और दक्षिण–पूर्व एशिया जैसे वैकल्पिक बाजारों की ओर रुख कर सकता है, जिससे उसका वैश्विक व्यापार में प्रभाव कम हो सकता है।

अमेरिकी विशेषज्ञ भी भारत के साथ टैरिफ युद्ध को गलत मानते हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा कि भारत के साथ व्यापारिक तनाव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने भारत के साथ संतुलित और पारस्परिक लाभकारी व्यापार वार्ताओं की वकालत की। राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ लिसा कर्टिस ने चेतावनी दी कि भारत पर उच्च टैरिफ लगाना अमेरिका की हिंद–प्रशांत रणनीति को कमजोर करेगा और चीन को क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने का मौका देगा। अमेरिकी चौंबर ऑफ कॉमर्स भी मानता है कि उच्च टैरिफ से अमेरिकी कंपनियां और उपभोक्ता प्रभावित होंगे।

ट्रंप की धमकियों के बीच रैपिडान एनर्जी ग्रुप के चेयरमैन बॉब मैकनेली का बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत पर रूस से तेल आयात के लिए 25ः से लेकर 100ः तक टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारत से रूसी तेल खरीदने की गुहार लगाई थी ताकि वैश्विक तेल की कीमतें नियंत्रित रहें। पूर्व अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी का एक वायरल वीडियो भी यही बात दोहराता है। गार्सेटी ने कहा कि भारत ने रूसी तेल इसलिए खरीदा क्योंकि अमेरिका चाहता था कि वह एक निश्चित मूल्य सीमा पर तेल खरीदे, जिससे वैश्विक बाजार में स्थिरता बनी रहे।

भारत ने इस दोहरे रवैये को उजागर करते हुए साफ कर दिया है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों और रणनीतिक हितों से समझौता नहीं करेगा। भारत क्वाड का प्रमुख स्तंभ है और हिंद–प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति को मजबूती देता है। भारत–अमेरिका आईसीईटी (पब्म्ज्) पहल के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, और रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ रहा है। भारत की तकनीकी क्षमता और मानव संसाधन अमेरिका के लिए अपरिहार्य हैं। भारत ने अमेरिका के लिए कृषि और डेयरी बाजार पूरी तरह खोलने से भी इनकार किया है, क्योंकि यह 70 करोड़ किसानों के हितों से जुड़ा है।

ट्रंप की बयानबाजी और धमकियां उनकी हताशा का प्रतीक हैं। वह भारत को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन साथ ही अपनी सामंती मानसिकता के कारण झुकना भी नहीं चाहते। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह दबाव में नहीं आएगा और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखेगा। आज की तारीख में भारत अमेरिका के लिए पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ट्रंप की नीतियां और बयानबाजी अमेरिका के लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। भारत ने न केवल अपनी आर्थिक और रणनीतिक ताकत का परिचय दिया, बल्कि वैश्विक मंच पर दोहरे मानदंडों को बेनकाब कर एक नया संदेश भी दिया है।

भारत-चीन आये साथ, तो एशिया की राजनीति में होगा बड़ा उलट फेर

भारत-चीन की नजदीकी के पीछे कई कारण हैं ट्रंप के टैरिफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका दिया, जिससे निर्यात प्रभावित हुआ। इसके जवाब में भारत ने चीन के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश की।

संजय सक्सेना
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रमुख व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने हाल ही में भारत–चीन संबंधों पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि चीन ने अक्साई चिन पर हमला किया था और वह भारत का दोस्त नहीं है। नवारो की यह प्रतिक्रिया भारत और चीन के बीच बढ़ती नजदीकी से जुड़ी है, जो अमेरिकी हितों को चुनौती दे रही है। ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद दोनों एशियाई दिग्गजों के रिश्ते सुधर रहे हैं, जिससे व्हाइट हाउस में खलबली मची हुई है। यह घटना वैश्विक भू–राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है, जहां अमेरिका चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर अड़ा हुआ है।

पीटर नवारो, जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में व्यापार नीति के प्रमुख सलाहकार हैं, ने एक साक्षात्कार में भारत को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, आप दशकों से चीन के साथ एक शांत युद्ध में हैं। चीन ने अक्साई चिन पर आक्रमण किया और आपके पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ये आपके दोस्त नहीं हैं। यह बयान सीधे तौर पर भारत–चीन के ऐतिहासिक विवादों को उजागर करता है और अमेरिकी चिंता को दर्शाता है कि भारत की चीन से नजदीकी क्वाड गठबंधन को कमजोर कर सकती है, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। अक्साई चिन का मुद्दा भारत–चीन संबंधों का एक पुराना घाव है। 1962 के भारत–चीन युद्ध में चीन ने अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया, जो लद्दाख क्षेत्र का हिस्सा है। यह क्षेत्र लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और चीन इसे शिनजियांग प्रांत का हिस्सा मानता है। युद्ध में भारत को भारी नुकसान हुआ, जिसमें हजारों सैनिक मारे गए। उसके बाद से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद जारी है। 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प ने संबंधों को और बिगाड़ दिया, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। लेकिन हाल के महीनों में स्थिति बदल रही है। 2025 में ट्रंप के टैरिफ हमले के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक गुप्त पत्र भेजा, जिसने संबंधों को पुनर्जीवित किया।

ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। नवारो ने इसे ष्मोदी का युद्ध कहा, मतलब यूक्रेन–रूस संघर्ष को भारत की वजह से लंबा खींचना। उन्होंने कहा, भारत इतना अहंकारी है (रूसी तेल खरीदने पर)। वे कहते हैं कि हम जहां से चाहें तेल खरीद सकते हैं। भारत, आप दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। वैसा ही व्यवहार करें! नवारो ने सुझाव दिया कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, तो अमेरिका 25 प्रतिशत टैरिफ माफ कर सकता है। लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा नीति को स्वतंत्र रखा है, जो अमेरिकी दबाव को चुनौती देता है।

भारत–चीन की नजदीकी के पीछे कई कारण हैं। ट्रंप के टैरिफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका दिया, जिससे निर्यात प्रभावित हुआ। इसके जवाब में भारत ने चीन के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश की। हाल ही में दोनों देशों ने सीमा पर गश्त समझौते किए, प्रत्यक्ष उड़ानें बहाल कीं और पर्यटन को बढ़ावा दिया। मोदी की दुर्लभ चीन यात्रा की चर्चा है, जो शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नई दोस्ती एशिया में व्यापार को बदल सकती है और अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधनों को कमजोर कर सकती है। अलजजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप के टैरिफ और भू–राजनीतिक बदलाव ने भारत–चीन को करीब लाया है, जो क्वाड को नुकसान पहुंचा सकता है।

गौरतलब हो, ट्रंप प्रशासन चीन को वैश्विक खतरा मानता है और भारत को उसके खिलाफ मोर्चे पर रखना चाहता है। लेकिन भारत की रणनीतिक स्वायत्तता नीति अमेरिका को पसंद नहीं आ रही। भारत रूस से एस–400 मिसाइल सिस्टम खरीद चुका है।

राजस्थानः अब साल में केवल छह माह ही चलेंगे ईंट-भट्टे, सरकार ने जारी किए आदेश

पहले ईंट–भट्टों का संचालन नौ महीने तक होता था, लेकिन अब सरकार ने नए आदेश जारी करते हुए इन्हें केवल 1 जनवरी से 30 जून तक चलाने की अनुमति दी है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक भट्टों पर फायरिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निर्माण कार्य महंगे हुए

22 जनवरी 2025 को जारी आदेश का असर 1 जुलाई से साफ दिखाई देने लगा है। चित्तौड़गढ़ जिले समेत पूरे प्रदेश में ईंटों की सप्लाई घट गई है। नतीजतन, ईंटों की कीमतें एक से सत्रह सौ रुपए तक बढ़ गई हैं। अब एक ट्रैक्टर ईंट मंगवाने पर आमजन को करीब 3000 से 3500 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। इससे मकान निर्माण से लेकर सरकारी योजनाओं तक सभी कामों पर सीधा असर पड़ा है।

चित्तौड़गढ़ की ईंटों की प्रदेशभर में मांग

चित्तौड़गढ़ के 125 से अधिक चिमनी ईंट–भट्टों से बनी ईंटें न केवल जिले में बल्कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, सलूंबर और उदयपुर तक भेजी जाती हैं। यहां लगभग 10 से 15 हजार मजदूर काम करते थे, जो काम बंद होने पर अपने गांव लौट गए हैं। वे 31 दिसंबर के बाद वापस लौटना शुरू करेंगे। भट्टा संचालकों का कहना है कि 7 रुपए प्रति ईंट की दर पर यहां की ईंटें चूरू और हनुमानगढ़ से आने वाली सस्ती ईंटों की तुलना में महंगी हैं, हालांकि गुणवत्ता बेहतर होने से बड़े निर्माण कार्यों में इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है।

कीमतों में भारी बढ़ोतरी

- कोयले से बनी ईंटेंरू पहले 1000 ईंटें 5000 रुपए में मिलती थीं, अब 6500 रुपए तक।
- तुड़ी व लकड़ी से बनी ईंटेंरू पहले 5000 रुपए प्रति हजार, अब 6000 रुपए।
- मिट्टी से बनी ईंटेंः पहले 5300 रुपए प्रति हजार, अब 7000 रुपए।

यह अचानक बढ़ी हुई कीमतें ठेकेदारों, मिस्त्रियों और घर बनाने वाले लोगों के बजट को बिगाड़ रही हैं।

मई में ही थमा काम

इस बार मई में जल्दी बारिश होने से भट्टों का काम 15 दिन पहले ही बंद करना पड़ा। स्टॉक कम होने के कारण सप्लाई और घट गई। मजदूर भी काम बंद होने पर गांव लौट गए, जो साल के अंत तक वापस आना शुरू करेंगे।

कवयित्री प्रज्ञा श्रीवास्तव प्रज्ञाञ्जलि

शरारती चाँद

आज आसमान नीला नही था
झक्क बादलों से भरा
भूरे काले रंग वाले
शरारती चाँद
रातभर खेलता रहा
लुका-छिपी
कभी बूंदें बरसती
कभी बिजली चमकती
गड़गड़ाहट की आवाज से
डर रही थी पूसी
आंगन में लगा गुलमोहर पेड़
भीग कर खुश हो रहा था
चंपा,गुलाब, मोगरे
कुछ गुनगुना रहे थे
मीठा सा
मिट्टी की सौंधी महक
आह!मन के भीतर
समा गई
सच्ची
लहराते हवा के झोंके
बहक रहे थे
जगते रहे मेरे ख्वाब
और मैं भी

RNI No. UTTHIN/2021/80704

प्रकाशन की तिथि- प्रत्येक माह की 7 तारीख
प्रेषण दिनांक- प्रत्येक माह की 10 तारीख

विभिन्न विषयों पर आधारित राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

तीर निशाने पर

विशिखा

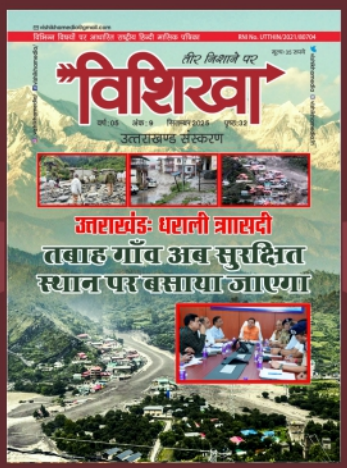

सदस्यता शुल्क (उत्तराखंड संस्करण)

				आपका फायदा
मूल्य प्रति कॉपी	35/-	35/- मात्र	0	0
एक वर्ष हेतु	420/-	385/-मात्र	11 महीने + 1 महीने मुफ्त	35/-
दो वर्ष हेतु	840/-	750/-मात्र	22 महीने + 2 महीने मुफ्त + 20/-	90/-

Paytm
9587455444

BANK DETAILS-
A/C No. – 6345002100000139
IFSC Code- PUNB0634500
A/C Off- VISHIKHA MEDIA
Bank - Punjab National Bank , Branch - NRI Circle, JAIPUR

विशिखा में विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें

तीन निशाने पर... विशिखा

मुख्यालय : विशिखा मीडिया 191/56, सेक्टर–19, प्रताप नगर, सांगानेर
जयपुर–302033 (राज.)
Contact us: +911413562171, 9587455444
E-mail: vishikhamedia@gmail.com | **Website:** www.vishikhamedia.in
vishikhamedia/ _vishikhamedia/ vishikhamedia